



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2019/आषाढ़ 3, 1941

No. 381]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2019/ASADHA 3, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2019

सं. 26/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 450(अ).—जहां कि केन्द्र सरकार ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "पैरासीटामोल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, के आयात पर अधिसूचना संख्या 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए प्रतिपादन शुल्क लगाया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/16/2018-डीजीएडी, दिनांक 25 अप्रैल, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस प्रतिपादन शुल्क को जारी रखने के मामले की समीक्षा की है और उन्होंने इस विषयगत वस्तु पर प्रतिपादन शुल्क को 06 माह की अवधि तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या **39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **20 अगस्त, 2018**, जिसे सा.का.नि. **786 (अ)**, दिनांक **20 अगस्त, 2018** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड **3**, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त अधिसूचना संख्या **26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **28 अक्टूबर, 2013** में संशोधन करते हुए उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को **26 अप्रैल, 2019** तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दिया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के बारे में अधिसूचना संख्या **7/16/2018-डीजीएडी**, दिनांक **29 जनवरी, 2019** में प्रकाशित दिनांक **29 जनवरी, 2019** के अपने अंतिम निष्कर्षों में उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त किए जाने के लिए सिफारिश की थी :

और जहां कि इन अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने अधिसूचना संख्या **19/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **16 अप्रैल, 2019**, जिसे सा.का.नि. **309 (अ)**, दिनांक **16 अप्रैल, 2019** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड **3**, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या **39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **20 अगस्त, 2018** को निरस्त करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त अंतिम निष्कर्षों के अनुसार विषयगत वस्तु पर लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया था;

और जहां कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एससीए संख्या **5278/2019** के मामले में अपने दिनांक **24.04.2019** के आदेश के द्वारा उपर्युक्त अधिसूचना संख्या **39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **28.08.2018** को **24.06.2019** तक बढ़ाए जाने का निर्देश दिया था और जब उसको यह बताया गया कि उक्त अधिसूचना संख्या **39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **20 अगस्त, 2018** को अधिसूचना संख्या **19/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **16 अप्रैल, 2019** के द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस मुख्य याचिका के अंतिम निपटान तक अधिसूचना संख्या **19/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **16 अप्रैल, 2019** को आस्थगित कर दिया था;

और जहां कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एससीए संख्या **5278/2019** के मामले में अपने दिनांक **09.05.2019** के आदेश के तहत निर्देश दिया था कि अधिसूचना संख्या **39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **20.08.2018** को **24.06.2019** तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) **13302-13304/2019** के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती दी है;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक **09.05.2019** के निर्णय के अनुपालन में अधिसूचना संख्या **22/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **10 जून, 2019** के द्वारा अधिसूचना संख्या **39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)** को **24.06.2019** तक की अवधि आगे बढ़ा दिया है;

जहां कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एससीए संख्या **5278/2019** के मामले में अपने दिनांक **20.06.2019** के आदेश में यह निर्देश दिया है कि अधिसूचना संख्या **39/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **20.08.2018**, को पुनः **09.07.2019** तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है बढ़ा दिया जाए;

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, **1995** के नियम **18** और **23** के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा **9** की उप धारा **(1)** और **(5)** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक **20.06.2019** को आए उच्च

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय और विशेष अवकाश याचिका (SLP) के अंतिम परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में तय किए जाने वाले पक्ष और अधिकारों के पक्षपात के बिना, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या **39/2018**, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक **20 अगस्त, 2018**, जिसे सा.का.नि. **786 (अ)**, दिनांक **20 अगस्त, 2018** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड **3**, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अंक, अक्षर और शब्द **"24 जून, 2019"** के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द **"09 जुलाई, 2019"** को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. **354/93/2001-टीआरयू (पार्ट.-4)**]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या **26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **28 अक्टूबर, 2013** को सा.का.नि. **710 (अ)**, दिनांक **28 अक्टूबर, 2013** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड **3**, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या **22/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)**, दिनांक **10 जून, 2019**, सा.का.नि. **415(अ.)**, दिनांक **10 जून, 2019** के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2019

No. 26 /2019-Customs (ADD)

G.S.R. 450(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination Injury) Rules, 1995, levied anti-dumping duty on imports of 'Paracetamol' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), *vide* notification No. 26/2013-Customs (ADD), dated the 28th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th October, 2013 for a period of five years from the date of publication in the Official Gazette;

And whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/16/2018-DGAD, dated the 25th April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty and recommended the extension of the anti-dumping duty on the subject goods for a period of six months;

And whereas, on the basis of the recommendations of the designated authority, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country up to and inclusive of the 26th April, 2019 *vide* notification No.39/2018-Customs (ADD), dated the 20th August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 786(E), dated the 20th August, 2018 amending aforesaid notification No. 26/2013-Customs (ADD), dated the 28th October, 2013;

And whereas, the designated authority in its final findings dated 29th January, 2019, published *vide* notification No. 7/16/2018-DGAD, dated the 29th January, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, regarding the review of anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject country, recommended termination of the anti-dumping duty on the import of subject goods;

And whereas on the basis of these final findings, the Central Government, *vide* notification No.19/2019-Customs (ADD), dated the 16th April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 309 (E), dated the 16th April, 2019; rescinded the notification of the Government of India, in the Ministry of

Finance (Department of Revenue), No. 39/2018-Customs (ADD), dated the 20th August, 2018 to terminate the levy of anti-dumping duty on the subject goods as per the said final findings of the designated authority;

And whereas the Hon'ble High Court of Gujarat in the matter of SCA No. 5278/2019 vide order dated 24th April, 2019, directed to extend the aforesaid notification No. 39/2018-Customs (ADD), dated the 20th August, 2018 till 24th June, 2019, and on being informed that the said notification No. 39/2018-Customs (ADD), dated 20th August, 2018 had already been rescinded vide notification No. 19/2019-Customs (ADD) dated the 16th April, 2019, the Hon'ble High Court suspended notification No. 19/2019-Customs (ADD) dated the 16th April, 2019, till final disposal of the main petition;

And whereas the Hon'ble High Court of Gujarat in the matter of SCA No. 5278/2019 vide order dated 09th May, 2019, again directed that the notification No. 39/2018-Customs (ADD), dated the 20th August, 2018 be extended for a further period up to 24th June, 2019;

And whereas the Central Government has challenged the aforesaid order vide Special Leave Petition No. 13302-13304/2019 in the Hon'ble Supreme Court;

And whereas the Central Government has extended notification No. 39/2018-Customs (ADD), dated the 20th August 2018 vide notification No. 22/2019-Customs (ADD) dated the 10th June, 2019, in pursuance of order of Hon'ble High Court of Gujarat dated 09th May, 2019;

And whereas the Hon'ble High Court of Gujarat in the matter of SCA No. 5278/2019 vide order dated 20th June, 2019, again directed that the notification No. 39/2018-Customs (ADD), dated the 20th August, 2018 be further extended up to and inclusive of 09th July, 2019;

Now therefore, in exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination Injury) Rules, 1995, and in pursuance of the High Court order dated 20th June, 2019, without prejudice to the rights and contentions of the parties to be decided in the writ petition before the Hon'ble High Court of Gujarat and the ultimate outcome of the SLP in the Hon'ble Supreme Court, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2018 Customs (ADD), dated the 20th August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G. S. R. 786 (E), dated 20th August, 2018, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and word "24th June, 2019", the figures, letters and word "9th July, 2019" shall be substituted.

[F.No.354/93/2001-TRU (Pt-IV)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification No.26/2013-Customs (ADD), dated the 28th October, 2013 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E), dated the 28th October, 2013 and last amended vide notification No. 22/2019-Customs (ADD) dated the 10th June, 2019, vide number G.S.R. 415(E), dated the 10th June, 2019.